>

Title: Related to proprietary right of plots allotted to landless people of Delhi.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही सेंसिटिव और दिल्ली के 10 लाख लोगों से जुड़ा हुआ मामला है । एमरजेंसी के दौरान कांग्रेस की सरकार थी । भूमिहीन लोगों को मकान बनाने के लिए प्लॉट्स दिए गए थे । उनको मकान दे दिए गए लेकिन मकान देने के बाद 10 सालों के शासन में यूपीए की सरकार ने 14 लाख लोगों को मकान बना कर दिए । हमारे प्रधान मंत्री जी ने डेढ़ करोड़ लोगों को मकान बना कर, बहनों को रजिस्ट्री उनके हाथ में दे दी । चालीस साल पुराने मकान, जो उनको दिए गए थे, आज तक उनको उनका मालिकाना हक नहीं दिया गया। वहां डेवेलपमेंट का काम नहीं होता है और सड़कें भी नहीं बनती हैं । वहां पर दिल्ली सरकार के अधिकारी बीडीओ वगैरह जाते हैं और उन गरीब लोगों से हफ्ता वसूली करते हैं ।

मेरा आपके माध्यम से दिल्ली सरकार से निवेदन है कि दिल्ली सरकार जो उन पर कुठाराघात कर रही है, उन लोगों ने खुल कर भारतीय जनता पार्टी को दिया है तो वे कह रहे हैं, जैसे वे लोग इनकी बपौती थे, उन्होंने उसको वोट दिया है तो उनको टॉर्चर किया जा रहा है । उन लोगों को मालिकाना हक मिलना चाहिए । असोला, अम्बेडकर नगर, आया नगर, लालकुआं, बिजवासन, इन कॉलोनियों में लैंडलेस लोगों को प्लॉट दिए गए है, उनको प्लॉट का मालिकाना देने के लिए सरकार कोशिश करे । मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. मनोज राजोरिया को श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।